

केंद्रीय बजट 2025-26: एक आकलन

आकाश राज, हर्षिता यादव,
कोवुरी आकाश यादव, आयुषी खंडेलवाल,
अनूप के सुरेश और समीर रंजन बेहरा द्वारा ^

केंद्रीय बजट 2025-26 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बजट में विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के तहत कई उपायों की घोषणा की गई। सरकार ने खपत को समर्थन देने के उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ, बजट ने राजकोषीय समेकन और विकास उद्देश्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित किया है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2025-26 विकास को गति देने, समावेशी विकास को सुरक्षित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है। चार प्रमुख चालक - कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात - विकास को गति देने के लिए परिकल्पित हैं, जिसमें नवाचार और सुधार महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बजट तत्काल सामाजिक-आर्थिक राहत और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन पर संतुलित ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि से लेकर शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तक दस विषयगत क्षेत्रों में लक्षित उपायों की तैनाती को रेखांकित करता है। बजट छह डोमेन - कराधान, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक ढांचे - में सुधार के एजेंडे को

^ इस लेख को तैयार करने में उनके समग्र मार्गदर्शन के लिए लेखक श्रीमती रेखा मिश्र के आभारी हैं। लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

स्पष्ट करता है ताकि समग्र कारक उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं पर केंद्रित ₹1 लाख करोड़ की कर राहत का प्रस्ताव है, जिससे घरेलू प्रयोज्य आय में वृद्धि होने तथा उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में, संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ सरलीकरण को लक्षित करते हैं तथा शुल्क व्युत्क्रमण को संबोधित करते हैं।

व्यय पक्ष पर, बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.2 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्षों में देखी गई गति को जारी रखता है। इसी तरह, प्रभावी पूंजीगत व्यय को 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में जीडीपी का 4.3 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया है। राजस्व व्यय 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 11.4 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (बजट अनुमान) में 11.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य सरकारों को अपने स्वयं के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता' को ₹1.5 लाख करोड़ के प्रावधान के साथ बढ़ाया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 (बीई) में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लक्षित करके विकास की अनिवार्यताओं को राजकोषीय विवेक के साथ संतुलित करता है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान (आरई) 4.8 प्रतिशत से कम है, जो 2025-26 तक जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने उद्देश्य पर कायम है। 2026-27 से आगे, सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को उस प्रक्षेपवक्र पर बनाए रखना है जो सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट सुनिश्चित करता है, जो मार्च 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

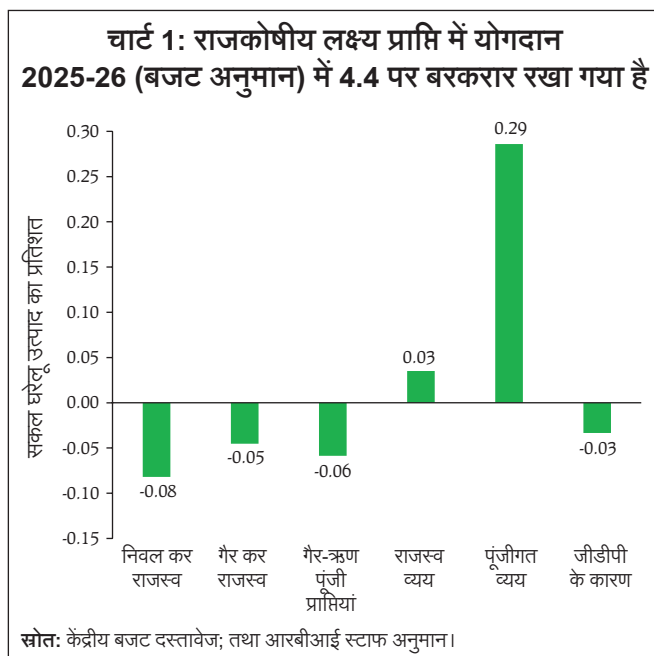
इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग आठ खंडों में विभाजित है। खंड II में राजकोषीय घाटे के अंतर्निहित कारकों की चर्चा है, इसके बाद खंड III और IV में क्रमशः राजस्व और व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। खंड V में सरकार की बकाया ऋण स्थिति की रूपरेखा दी गई है, जबकि खंड VI में राजकोषीय घाटे

के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड VII में राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण की जांच की गई है, जबकि खंड VIII में अंतिम टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के बजटीय जीएफडी के मुकाबले संशोधित अनुमान 4.8 प्रतिशत रखा गया है। 10 आधार अंकों का समेकन मुख्य रूप से बजटीय पूंजीगत व्यय से कम होने के कारण है (चार्ट 1)।

2025-26 (बजट अनुमान) के लिए जीएफडी जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है।¹ 2025-26 (बजट अनुमान) बनाम 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए 45 आधार अंकों के परिकल्पित समेकन को राजस्व व्यय को जीडीपी के 11.0 प्रतिशत [2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.4 प्रतिशत से] पर सीमित करके और पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जबकि सकल कर राजस्व को जीडीपी के 12.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान में जीडीपी के 11.9 प्रतिशत से) [सारणी 1]। राजस्व व्यय-पूंजीगत परिव्यय (आरई-सीओ) अनुपात-व्यय की गुणवत्ता का एक सारांश संकेतक -



¹ केंद्रीय बजट में 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 356,97,923 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 7 जनवरी, 2025 को जारी 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) 324,11,406 करोड़ रुपये से 10.1 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक²

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2023-24	2024-25		2025-26
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	5.6	4.9	4.8	4.4
2. प्राथमिक घाटा	2.0	1.4	1.3	0.8
3. राजस्व घाटा	2.6	1.8	1.9	1.5
4. प्रभावी राजस्व घाटा	1.6	0.6	1.0	0.3
5. सकल कर राजस्व	11.7	11.8	11.9	12.0
6. गैर-कर राजस्व	1.4	1.7	1.6	1.6
7. राजस्व व्यय	11.8	11.4	11.4	11.0
8. पूंजीगत व्यय	3.2	3.4	3.1	3.1
जिसका कि:				
(i) पूंजीगत परिव्यय	2.7	2.8	2.6	2.5
9. प्रभावी पूंजीगत व्यय	4.2	4.6	4.1	4.3
10. ऋण	58.7	56.8	57.1	56.0

टिप्पणी: 1. प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के बीच का अंतर है।

2. पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम राशि घटाई जाती है।

3. प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता का योग होता है।

4. बीई का अर्थ बजट अनुमान है, आरई का अर्थ संशोधित अनुमान है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

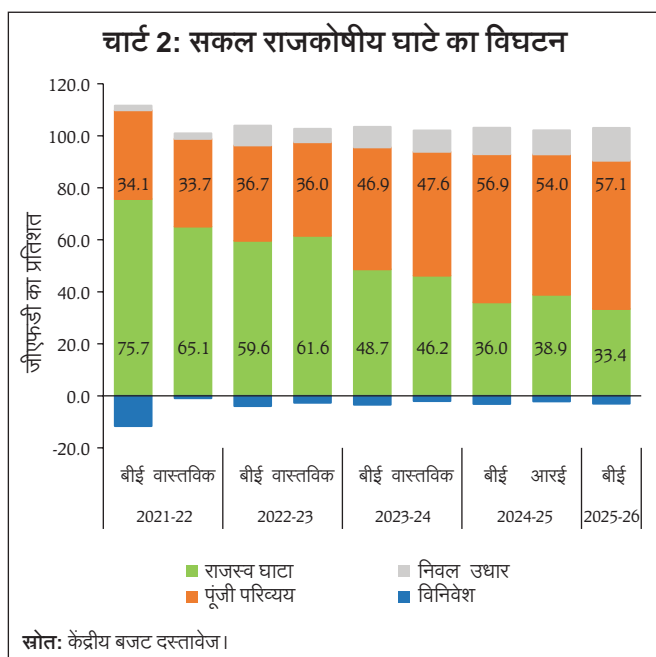
जीएफडी का अपघटन

राजस्व घाटे (आरडी) द्वारा विनियोजित जीएफडी का हिस्सा 2018-19 से 2023-24 के दौरान औसतन लगभग 65.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 38.9 प्रतिशत रह गया, जिसे 2025-26 में और भी कम करके 33.4 प्रतिशत करने का बजट है। इसके साथ ही, जीएफडी में वृद्धि-प्रेरक पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 54.0 प्रतिशत हो गया है और 2025-26 (बजट अनुमान) में 57.1 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2018-19 से 2023-24 के दौरान औसतन लगभग 35.2 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

III. प्राप्ति

कुल गैर-ऋण प्राप्ति में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह सकल घरेलू उत्पाद का 9.7 प्रतिशत रहा। कर राजस्व में मजबूत वृद्धि, रिजर्व बैंक से उच्च अधिशेष हस्तांतरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बेहतर लाभांश आय ने 2023-24 की तुलना में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में प्राप्ति के बेहतर प्रदर्शन को समर्थन दिया। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए, सरकार को उम्मीद है कि गैर-ऋण प्राप्ति अपनी गति बनाए रखेगी, जो

² विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक देखें।

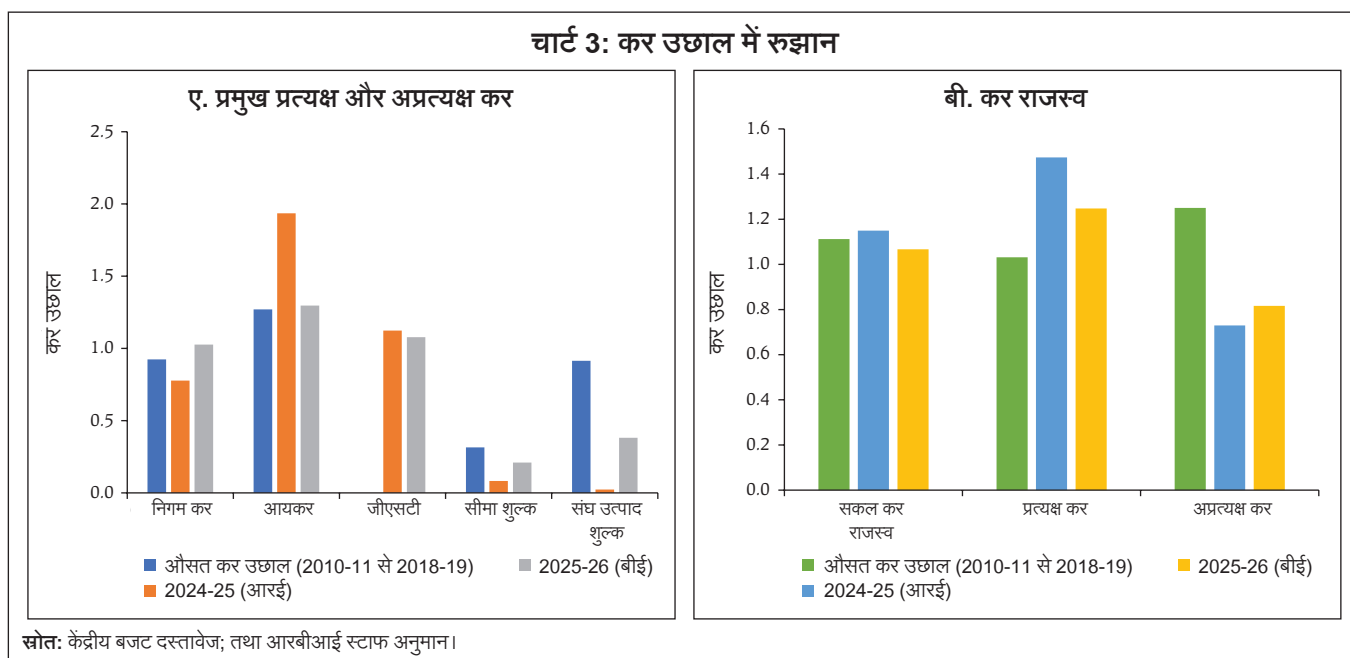


2024-25 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। 2025-26 में सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, साथ ही गैर-कर राजस्व में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। राज्यों को 2024-25 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2025-26 (बजट अनुमान) में शुद्ध कर राजस्व में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

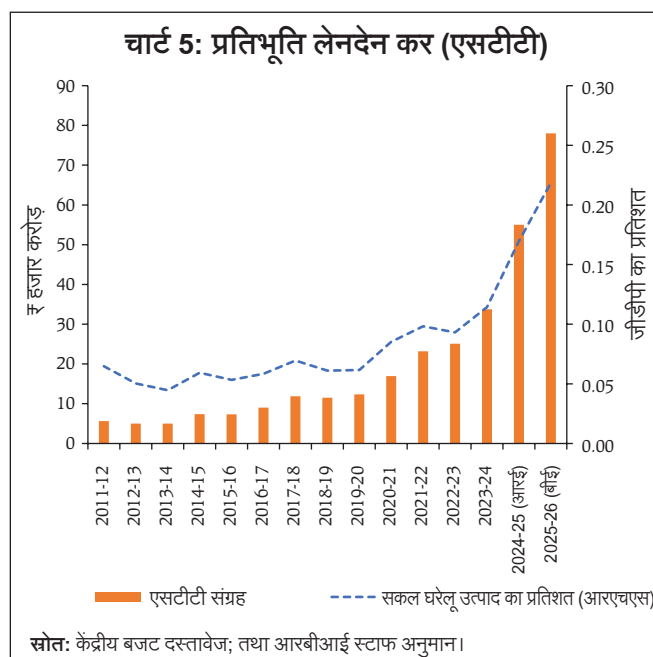
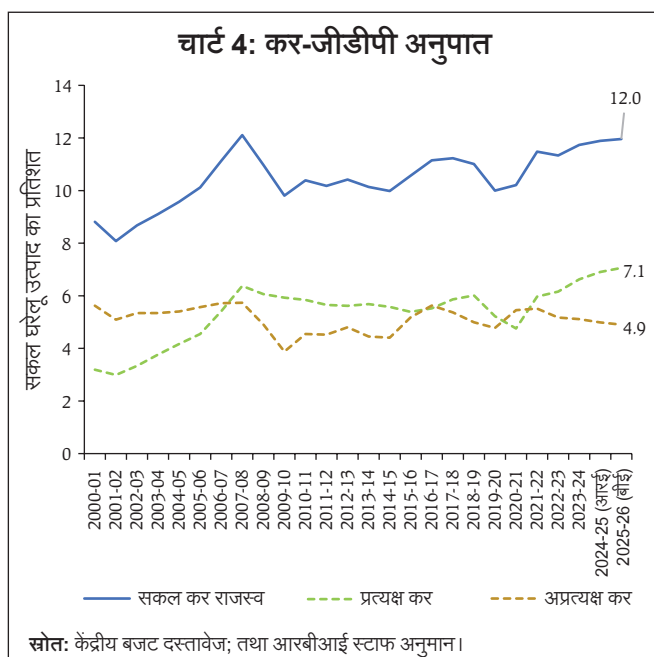
कर राजस्व

आयकर और जीएसटी संग्रह के कारण सकल कर राजस्व में 2023-24 की तुलना में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2025-26 के लिए, सरकार ने सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट बनाया है, जिसमें कर उछाल मोटे तौर पर 2010-11 से 2018-19 के दौरान औसत के अनुरूप बना हुआ है। प्रत्यक्ष करों की उछाल 2025-26 (बजट अनुमान) में 1.25 से कम रखी गई है, जबकि 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 1.47 है, जो आयकर राहत को दर्शाता है, जबकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में लाभ के कारण अप्रत्यक्ष करों की उछाल 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 0.73 से 2025-26 (बजट अनुमान) में 0.82 तक ठीक होने की उम्मीद है (चार्ट 3ए और बी)।

सकल कर-जीडीपी अनुपात को 2025-26 में 12.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है, जो 2007-08 के बाद सबसे अधिक है (चार्ट 4)। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर-मुक्त आय सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी आय वर्गों में कर स्लैब को संशोधित किया गया है। कर राहत से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होने और घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विभिन्न उपायों के कारण कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में ₹2,600 करोड़ का अनुमान है।³



³ जैसा कि वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में उल्लेख किया गया है।



प्रत्यक्ष कर

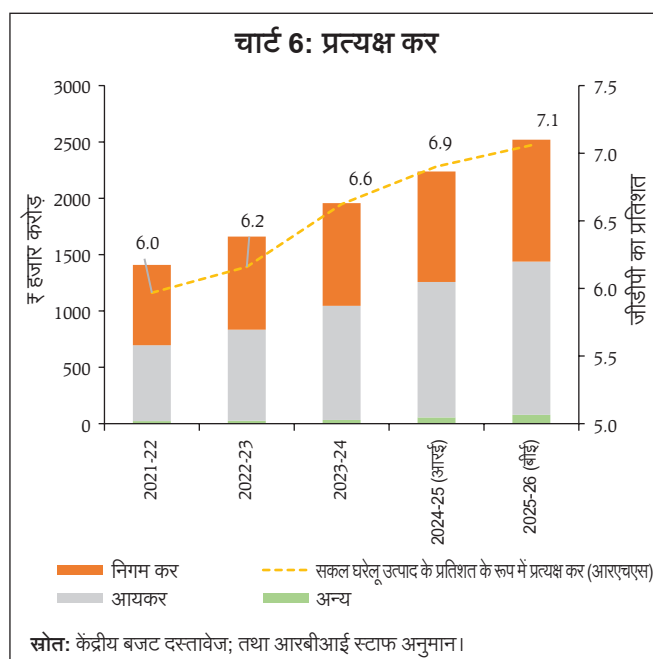
14.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2024-25 (संशोधित अनुमान) में प्रत्यक्ष कर बजट अनुमानों से ₹30,000 करोड़ अधिक हो गए। आयकर राजस्व में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजट अनुमान की तुलना में कॉर्पोरेट कर संग्रह में ₹40,000 करोड़ की कमी की भरपाई हुई। 2024-25 (संशोधित अनुमान) के दौरान, प्रतिभूति लेनदेन कर ने अपने बजट अनुमान ₹37,000 करोड़ से 48.6 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया; 2025-26 (संशोधित अनुमान) में इसे 41.8 प्रतिशत और बढ़ाने का बजट है [चार्ट 5]।

2025-26 (बीई) के लिए, प्रत्यक्ष कर राजस्व में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि आयकर और कॉर्पोरेट कर में वृद्धि क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत होगी (चार्ट 6)। बजट में अनुपालन को बढ़ावा देने और कर आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरलीकरण और युक्तिकरण उपायों की घोषणा की गई है।

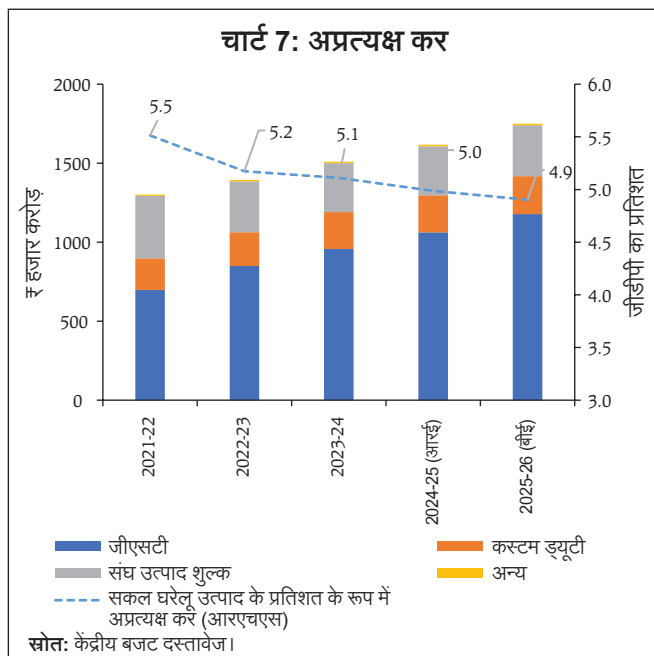
अप्रत्यक्ष कर

2024-25 (संशोधित अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजटीय राशि से कम रहा, मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹14,000 करोड़ की

कमी के कारण।⁴ जीएसटी संग्रह बजट अनुमानों के अनुरूप था। 2025-26 (बजट अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि क्रमशः 10.9 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 7)।

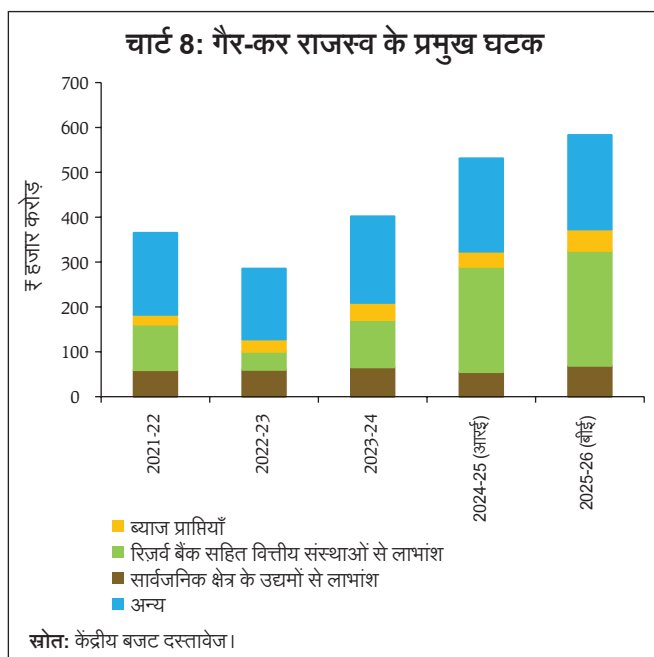


⁴ केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का कारण विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसआईडी) के तहत ₹7,460 करोड़ की कमी थी। जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन और पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर एसआईडी की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर 2024 में इसे रद्द कर दिया गया (स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ; और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)।



गैर-कर राजस्व

रिजर्व बैंक से अधिक अधिशेष हस्तांतरण के समर्थन से, गैर-कर राजस्व ने 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए, गैर-कर राजस्व वृद्धि 9.8 प्रतिशत रखी गई है, जिसका नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से लाभांश और मुनाफे में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि और रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 9.3 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा किया गया है (चार्ट 8)।

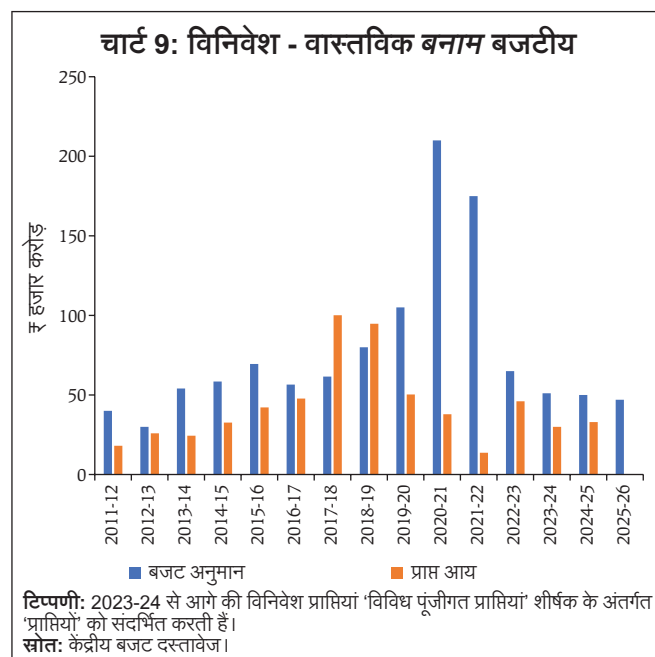


गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति

2024-25 (संशोधित अनुमान) में गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति बजट अनुमान से ₹19,000 करोड़ कम रहीं, जिसका मुख्य कारण कम विनिवेश प्राप्ति थीं। 2025-26 (बजट अनुमान) में गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, जिसमें विनिवेश लक्ष्य ₹47,000 करोड़ है (चार्ट 9)।

IV. व्यय

केंद्र सरकार के कुल व्यय में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, और यह मुख्य रूप से आवंटित पूंजीगत व्यय के कम उपयोग के कारण बजट अनुमान से 1.04 लाख करोड़ रुपये कम था (सारणी 2)। इसके विपरीत, राजस्व व्यय बजट अनुमानों के अनुरूप था और 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए कुल व्यय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 14.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। पूंजीगत व्यय में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुधार होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान में 42.4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभावी पूंजीगत व्यय में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2025-26 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का बजट है। बजट में 2024-25 (बीई) की तरह 2025-26 (बीई) में भी 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन बरकरार रखा गया है। राजस्व



सारणी 2: केंद्र सरकार का व्यय

मद	₹ हजार करोड़				सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कुल व्यय	4,443	4,821	4,716	5,065	15.0	14.8	14.6	14.2	6.0	6.1	7.4
2. राजस्व व्यय (आरई) (जिसका कि)	3,494	3,709	3,698	3,944	11.8	11.4	11.4	11.0	1.2	5.8	6.7
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	1,064	1,163	1,138	1,276	3.6	3.6	3.5	3.6	14.6	7.0	12.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस) जिसका कि:	435	428	428	426	1.5	1.3	1.3	1.2	-24.7	-1.6	-0.4
खाना	212	205	197	203	0.7	0.6	0.6	0.6	-22.4	-6.8	3.0
उर्वरक	188	164	171	168	0.6	0.5	0.5	0.5	-25.1	-9.0	-2.0
पेट्रोलियम	12	12	15	12	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5	20.1	-17.7
(iii) आरई-आईपी-टीएस	1,995	2,118	2,132	2,242	6.8	6.5	6.6	6.3	2.5	6.9	5.1
(v) रक्षा (राजस्व)	303	298	313	328	1.0	0.9	1.0	0.9	12.7	3.3	4.8
3. पूंजीगत व्यय	949	1,111	1,018	1,121	3.2	3.4	3.1	3.1	28.3	7.3	10.1
4. प्रभावी पूंजीगत व्यय	1,253	1,502	1,318	1,548	4.2	4.6	4.1	4.3	19.8	5.2	17.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

व्यय में 6.7 प्रतिशत और आरई-आईपी-टीएस में 5.1 प्रतिशत (जीडीपी का 6.3 प्रतिशत) की वृद्धि का बजट रखा गया है।

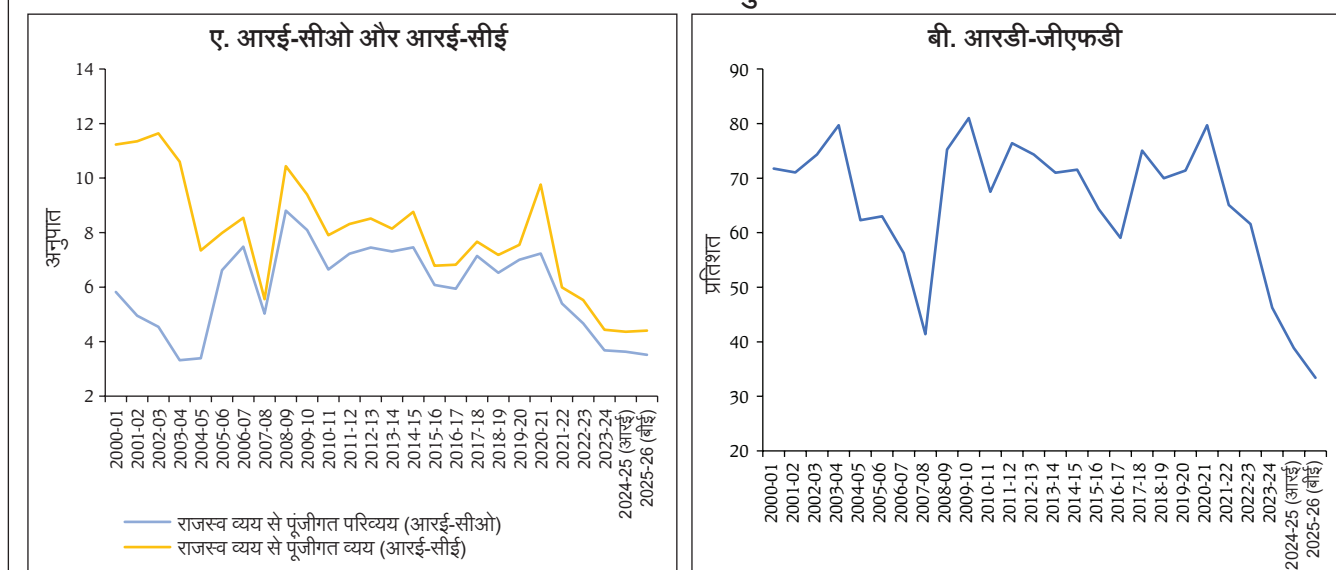
व्यय की गुणवत्ता

राजस्व व्यय - पूंजीगत परिव्यय (आरई-सीओ) अनुपात 2024-25 (आरई) और 2025-26 (बीई) दोनों में 4.4 पर अपने सबसे निचले स्तर पर रहा। सकल राजकोषीय घाटे (आरडी-जीएफडी) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा भी 33.4 प्रतिशत के अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर रहा, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है (चार्ट 10ए और बी)।

पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 7.6 प्रतिशत बढ़ा। यह बजट लक्ष्य से ₹70,959 करोड़ कम रहा, अन्य बातों के अलावा, आम चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता और मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण। 2025-26 (बजट अनुमान) में पूंजीगत व्यय में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है (सारणी 3)। रेलवे, सड़क और पुलों के पूंजीगत व्यय - केंद्र के पूंजीगत व्यय के प्रमुख

चार्ट 10: व्यय की गुणवत्ता



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सारणी 3: पूंजीगत परिव्यय							
मद	₹ हजार करोड़				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल पूंजी परिव्यय	788	919	848	895	26.1	7.6	5.6
2. रक्षा सेवाएँ	154	172	160	180	7.9	3.4	12.9
3. पूंजीगत परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	634	747	688	715	31.6	8.6	3.9
(i) प्रमुख बुनियादी ढांचा (जिनमें से)	576	600	590	573	34.7	2.4	-2.9
भारतीय रेल	243	252	252	252	52.3	3.9	0.0
सड़कें और पुल	270	259	259	259	28.2	-4.1	0.1
संचार	61	84	75	50	8.8	24.0	-33.1
(ii) उद्योग एवं खनिज	6	6	13	12	-3.6	97.7	-3.1
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	7	7	6	8	-8.1	-10.6	27.0
(iv) अन्य	44	133	79	122	11.2	80.0	54.3

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चालक - को 2025-26 (बजट अनुमान) में उनके 2024-25 (संशोधित अनुमान) स्तरों पर बनाए रखा गया है।

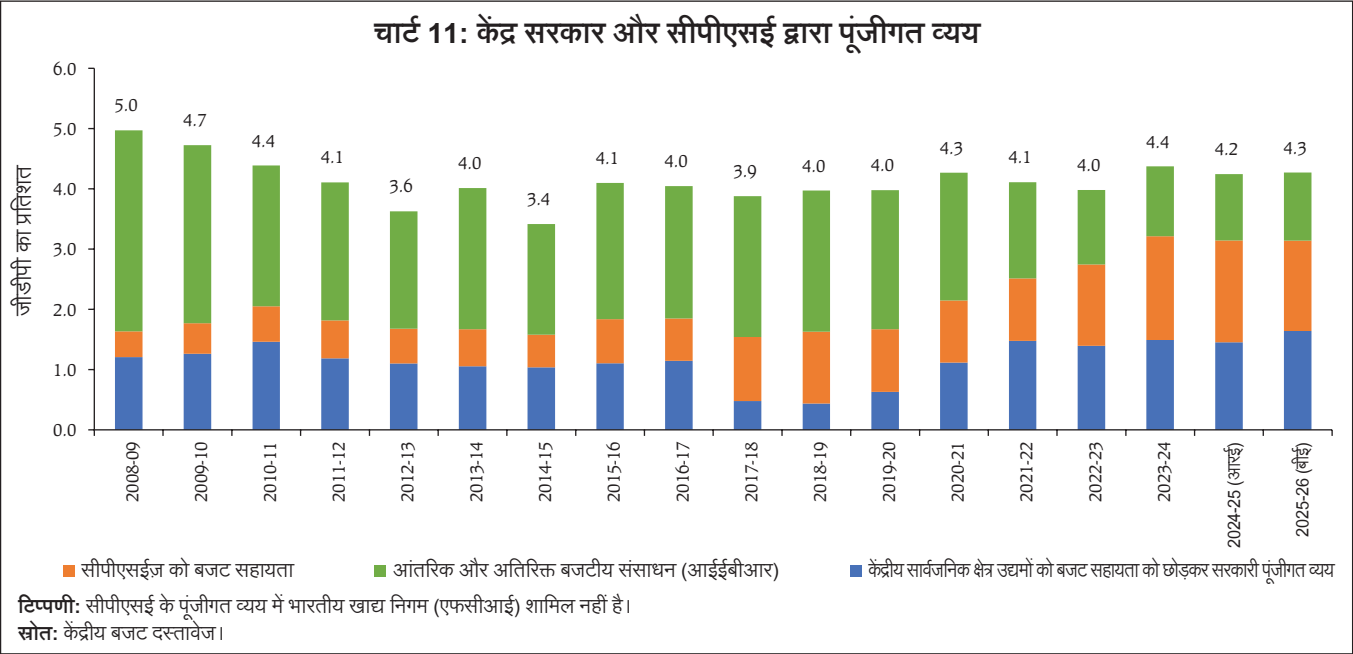
केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संयुक्त पूंजीगत व्यय

से वित्तपोषित करते हैं, जो सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार और सीपीएसई का संयुक्त पूंजीगत व्यय 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 4.2 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत हो जाएगा [चार्ट 11]।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने पूंजीगत व्यय को आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर)⁵ और केंद्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम

प्रमुख सरकारी योजनाएँ

केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में, पीएमजीकेवाई को 2025-26 (बजट अनुमान) में कुल व्यय का 4.0 प्रतिशत [2024-25



⁵ आईईबीआर में आंतरिक संसाधन (प्रतिधारित लाभ - सरकार को लाभांश का शुद्ध लाभ, मूल्यहास प्रावधान और रिजर्व और अधिशेष को आगे ले जाना) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (बांड, डिबेंचर, बाहरी वाणिज्यिक उधार, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण, जमा प्राप्तियां और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण जारी करने से प्राप्तियां शामिल हैं) शामिल हैं। बजटीय सहायता और आईईबीआर मिलकर सीपीएसई के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का वित्तपोषण करते हैं।

सारणी 4: प्रमुख सरकारी योजनाओं पर व्यय

मद	₹ हजार करोड़				कुल व्यय का प्रतिशत			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं										
1. पीएम-किसान	61	60	64	64	1.4	1.3	1.3	5.5	3.4	0
2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	-	205	197	203	-	4.2	4.0	-	-	3.0
3. सड़क निर्माण कार्य	109	115	111	116	2.4	2.3	2.3	43.3	1.7	5.2
बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं										
1. मनरेगा	89	86	86	86	2.0	1.8	1.7	-1.8	-3.5	0.0
2. जल जीवन मिशन	70	70	23	67	1.6	0.5	1.3	28.0	-67.6	195.2
3. समग्र शिक्षा	33	38	37	41	0.7	0.8	0.8	1.0	12.7	11.5
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम*	25	29	29	30	0.6	0.6	0.6	2.8	15.8	4.3
5. प्रधान मंत्री आवास योजना	43	85	48	78	1.0	1.0	1.5	-41.0	9.5	64.1

टिप्पणी: 1. -: उपलब्ध नहीं।

2. *: आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

(संशोधित अनुमान) में 4.2 प्रतिशत] सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें परिव्यय 3.0 प्रतिशत बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ हो गया है। पीएम-किसान आवंटन पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा गया है; और सड़क कार्यों के परिव्यय को 5.2 प्रतिशत बढ़ाकर ₹1.16 लाख करोड़ कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, मनरेगा ₹86,000 करोड़ पर अपरिवर्तित है, जल जीवन मिशन का परिव्यय ₹67,000 करोड़ (195.2 प्रतिशत

वृद्धि) का बजट है। पीएम आवास योजना के परिव्यय में 64.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें केंद्र ने आवास पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है (सारणी 4)।

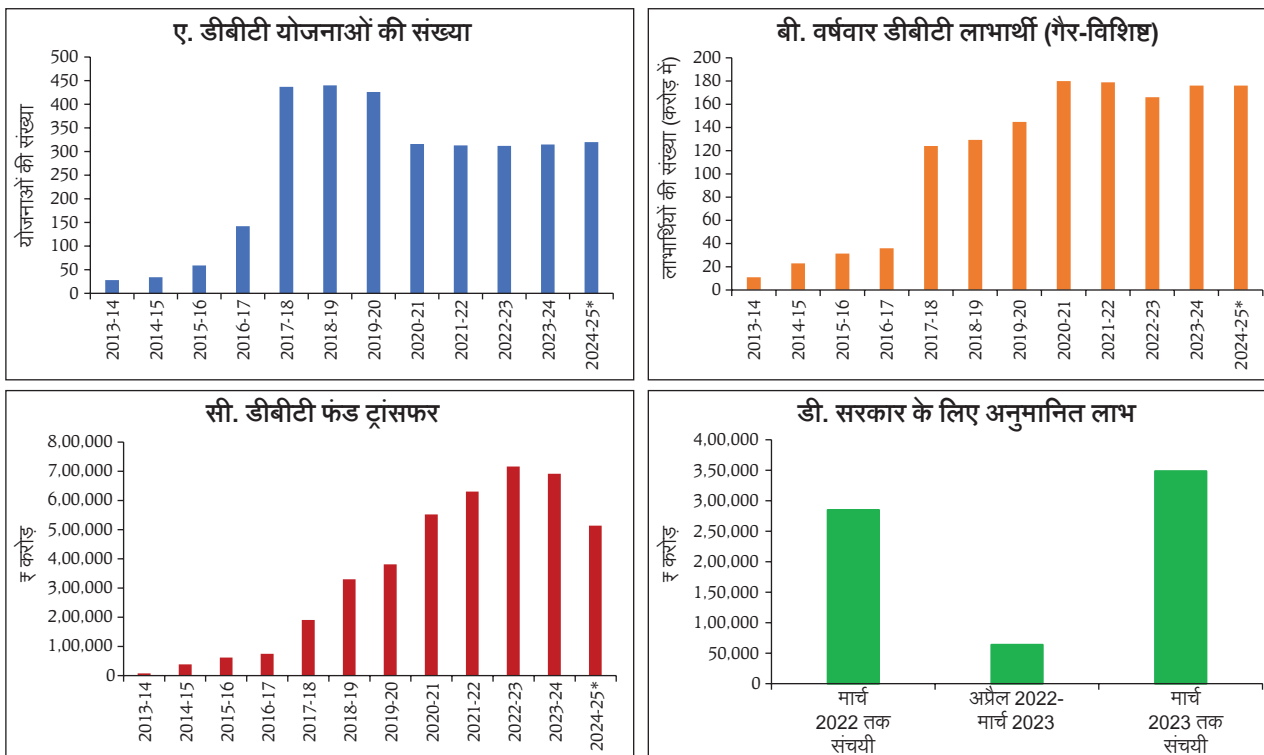
हाल के वर्षों में, डीबीटी तंत्र के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा धन हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की बचत हुई है (बॉक्स ए)।

बॉक्स ए: भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण – दशकीय अनुभव

भारत में, केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के लिए सामाजिक हस्तांतरण (जैसे, नकद और वस्तु हस्तांतरण) की एक विस्तृत श्रृंखला की देखरेख करती हैं। लीकेज को कम करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि इच्छित लाभार्थियों को न्यूनतम लागत पर समय पर हस्तांतरण मिले, केंद्र ने 2013 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) कार्यक्रम शुरू किया (परमासिवम और अरुण, 2018)। यह सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करता है, जिससे धन वितरण में बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य करने से दोहराव और लीकेज को रोका जा सकता है, जबकि आधार प्रणाली के साथ एकीकरण सत्यापन को मजबूत करता है (बरनवाल, 2016)।

डीबीटी को 1 जनवरी, 2013 को चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था, जिसमें शुरुआत में कुछ योजनाएं शामिल थीं। 2013 में ही, केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी भुगतान के लिए डीबीटी की शुरुआत की, इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस); राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस); और छात्र छात्रवृत्ति योजनाओं (परमासिवम और अरुण, 2018) जैसी प्रमुख योजनाएं शुरू की गईं। अगस्त 2015 तक, डीबीटी दुनिया का सबसे बड़ा नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बन गया, जिसने लगभग 14 करोड़ परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया (बरनवाल, 2016)। इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान, डीबीटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब भारत में (जारी)

चार्ट ए.1: भारत में डीबीटी की प्रगति



टिप्पणी: *: 2024-25 के लिए चार्ट में दर्शाए गए आंकड़े डीबीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर फरवरी 2025 के मध्य में उपलब्ध हैं।

स्रोत: <https://dbtbharat.gov.in/>

नकद हस्तांतरण की गति और पैमाना अभूतपूर्व था (भट्टाचार्य और सिन्हा, 2021)।

2013-14 में 28 योजनाओं की मामूली कवरेज से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के 54 मंत्रालयों में 323 योजनाओं में डीबीटी लागू किया गया है (चार्ट ए.1ए)। लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित धन में भी समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट ए.1बी और ए.1सी)। इसके अलावा, डीबीटी के तहत विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को शामिल करने से फर्जी और डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान और उन्हें हटाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बचत हुई है (चार्ट ए.1डी)।

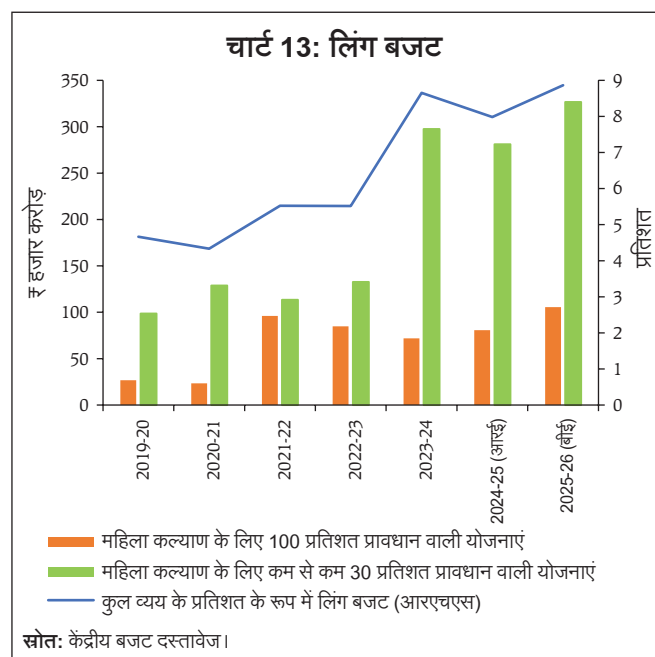
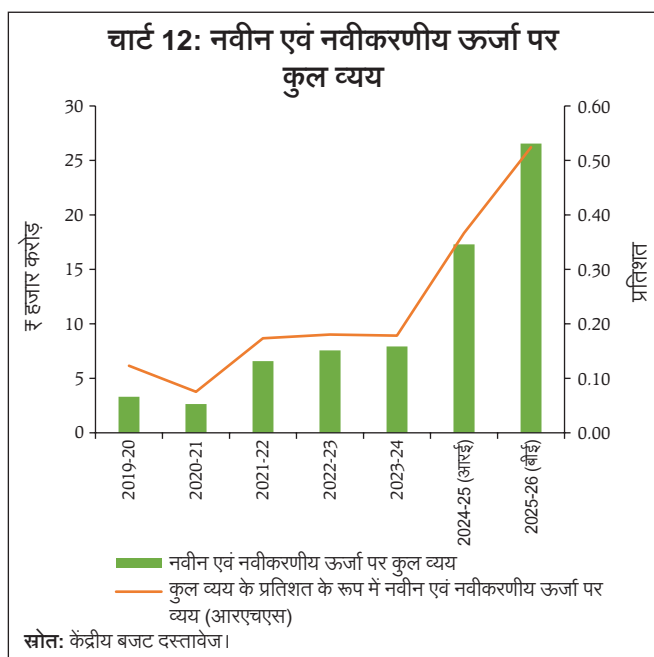
उदाहरण के लिए, डीबीटी के कार्यान्वयन ने उर्वरक विभाग को खुदरा विक्रेताओं को अपनी उर्वरक बिक्री में 158.1 लाख मीट्रिक टन की कमी करने में सहायता की है। इसी तरह, एमजीएनआरईजीएस के मामले में, डीबीटी के माध्यम से भुगतान ने 7.1 लाख फर्जी जॉब कार्ड को खत्म करने में मदद की है। इसी तरह, एलपीजी सब्सिडी भुगतान को डीबीटी के माध्यम से करने से 4.15 करोड़ नकली,

फर्जी या निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन समाप्त हो गए हैं।⁶ भारत द्वारा लागू किए गए डीबीटी-शैली के सार्वजनिक हस्तक्षेपों को विश्व बैंक द्वारा आपदा लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाने की सिफारिश की गई है (विश्व बैंक, 2022)।

संदर्भ:

1. Barnwal, P. (2016). Curbing Leakage in Public Programs with Direct Benefit Transfers: Evidence from India's Fuel Subsidies and Black Market. Department of Economics, Michigan State University. April.
2. Bhattacharya, S. and Sinha, R. (2021). Intent to Implementation: Summary of Lessons from Tracking India's Social Protection Response to COVID-19 (English). Washington, D.C.: World Bank Group.
3. Paramasivam, C. and Arunkumar, G. (2018). Direct Benefit Transfer: An Innovative Approach to Financial Inclusion in India. *JETIR*, 5(12), December.
4. World Bank. (2022). The Role of Digital in the COVID-19 Social Assistance Response (English). Washington, D.C.: World Bank Group.

⁶ डेटा मार्च 2023 तक का है और इसे <https://dbtbharat.gov.in/> से प्राप्त किया गया है।



नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर व्यय को 2024-25 (संशोधित अनुमान) में कुल व्यय का 0.37 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 (बजट अनुमान) में 0.52 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन में वृद्धि से किया गया है (चार्ट 12)। केंद्र सरकार के लिंग बजट को भी 2025-26 में अपने कुल व्यय का 8.9 प्रतिशत बढ़ाने का बजट बनाया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (चार्ट 13) द्वारा किया गया है।

V. बकाया ऋण

कोविड-19 महामारी के बीच 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 62.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार का कुल बकाया ऋण 2023-24 में 58.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 57.1 प्रतिशत हो गया और 2025-26 में इसे और घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 56.0 प्रतिशत होने का बजट है। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान का बजट 2025-26 में 37.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ब्याज दर-विकास दर अंतर (आईआरजीडी), जो ऋण स्थिरता का एक संकेतक है, अनुकूल बना हुआ है (चार्ट 14ए और बी)। आगे बढ़ते

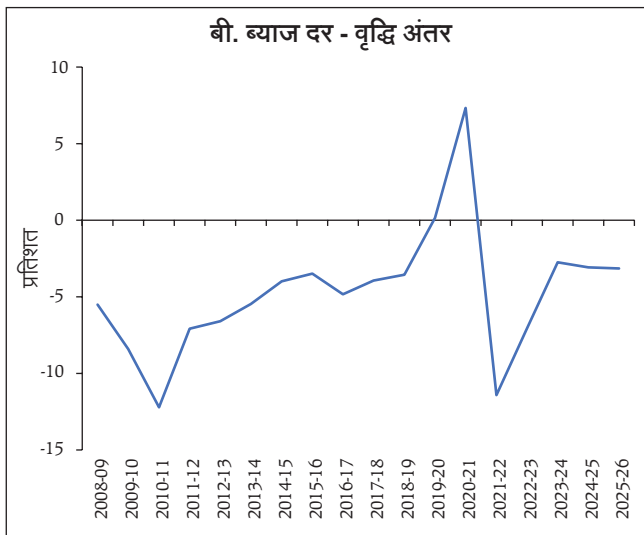
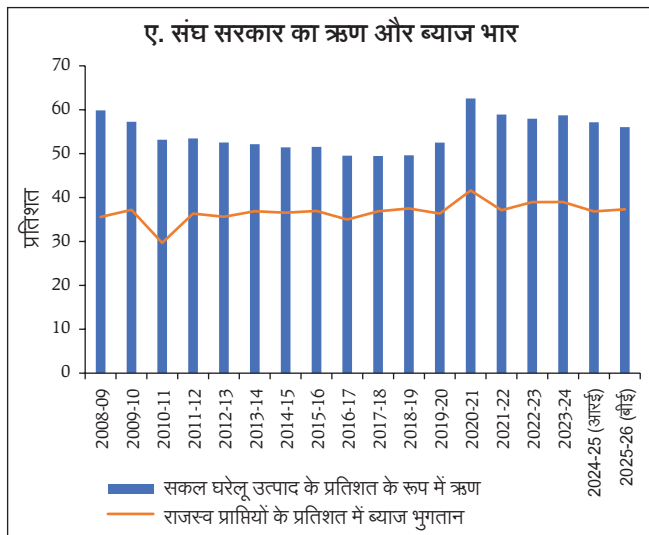
हुए, सरकार ने संकेत दिया है कि वह राजकोषीय घाटे के स्तर को बनाए रखेगी।

VI. सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण

वित्तपोषण के मामले में, 2025-26 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार ₹14.82 लाख करोड़ [2024-25 (संशोधित अनुमान) के ₹14.01 लाख करोड़ से लगभग 5.8 प्रतिशत की वृद्धि] का बजट रखा गया है। पिछले वर्ष के ₹10.75 लाख करोड़ की तुलना में शुद्ध बाजार उधार ₹11.54 लाख करोड़ रखा गया है।⁷ बजट में 2025-26 में कुल ₹2.50 लाख करोड़ की प्रतिभूतियों के सकल स्विच का भी प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह ₹1.47 लाख करोड़ था। सरकार ने 2025-26 के दौरान प्रतिभूतियों की किसी भी खरीद के लिए बजट नहीं रखा है। शुद्ध बाजार उधार से 2025-26 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 73.5 प्रतिशत वित्तपोषित होने की उम्मीद है लघु बचत (एनएसएसएफ) से 3.43 लाख करोड़ रुपये की राशि 2025-26 (बजट अनुमान) में जीएफडी के 21.9 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगी, जो 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 4.12 लाख करोड़ रुपये (26.2 प्रतिशत) से कम है [चार्ट 15]।

⁷ 2024-25 (संशोधित) के लिए निवल बाजार उधार के आंकड़ों में प्रतिभूतियों की वापस खरीद [₹ (-)88,164.01 करोड़] शामिल है।

चार्ट 14: बकाया देयताएं और ब्याज दर वृद्धि अंतर



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

केंद्र सरकार की बाजार उधार आवश्यकताओं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) को धीरे-धीरे महामारी-पूर्व स्तर तक कम करने से निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी (सारणी 5)।

VII. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

राज्यों को सकल हस्तांतरण में 2025-26 के लिए 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है [2024-25 (संशोधित

अनुमान) के दौरान 10.2 प्रतिशत], जो मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हस्तांतरण और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के कारण है। राज्यों को संसाधनों का सकल हस्तांतरण 2024-25 (संशोधित अनुमान) के दौरान

सारणी 5: केंद्र सरकार की बाजार उधारी

(₹ करोड़)

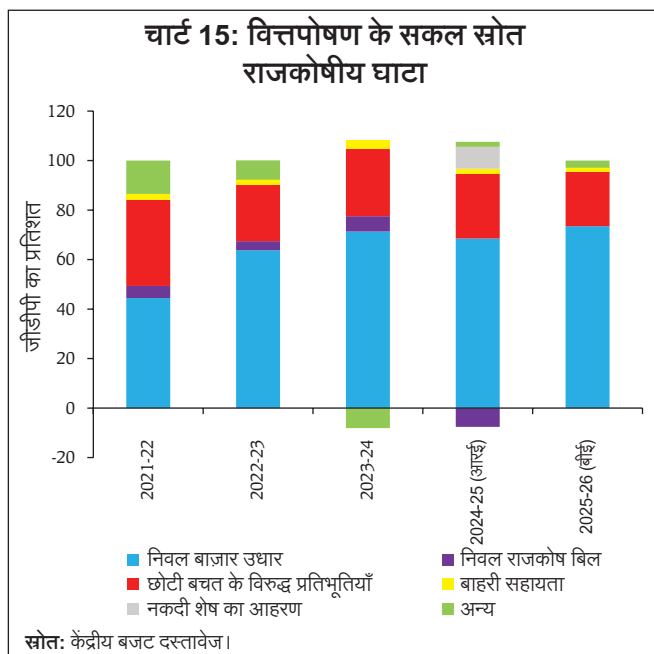
वित्तीय वर्ष	सकल बाजार उधार	निवल बाजार उधार
2018-19	5,71,000 (3.0)	4,22,735 (2.2)
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.3)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23	14,21,000 (5.3)	11,08,259 (4.1)
2023-24	15,43,000 (5.2)	11,77,754 (4.0)
2024-25 (आरई)	14,00,697 (4.3)	10,74,514 (3.3)
2025-26 (बीई)	14,82,000 (4.2)	11,53,834 (3.2)

टिप्पणी: 1. 2024-25 के लिए शुद्ध बाजार उधार (आरई) में प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद शामिल है।

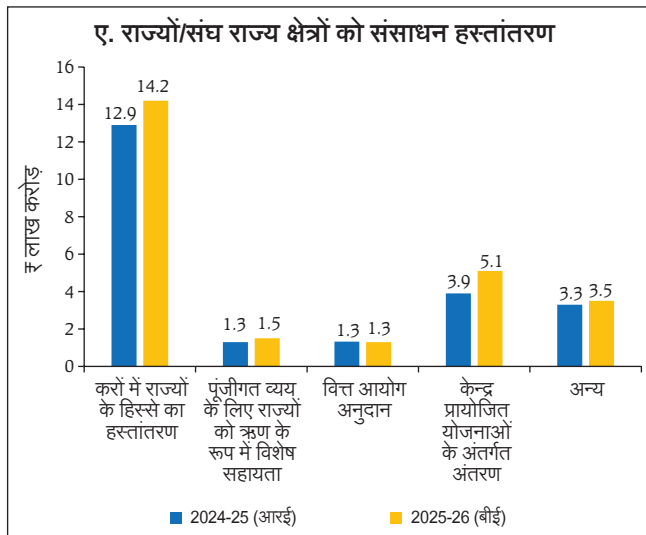
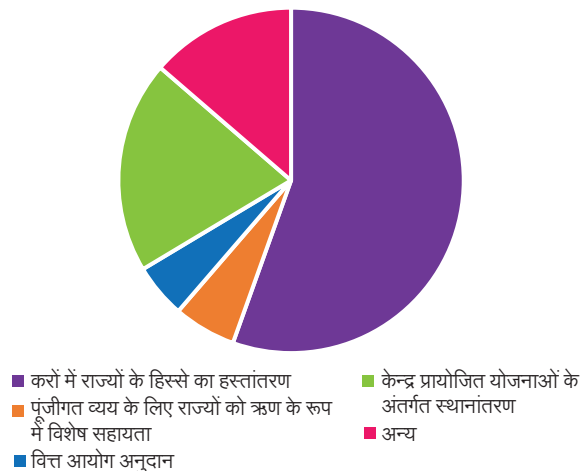
2. 2023-24 से, प्रतिभूतियों के स्विचिंग के लिए बाजार उधार को समायोजित किया गया है।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 16: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सकल संसाधन हस्तांतरण**बी. 2025-26 में राज्यों को सकल हस्तांतरण में हिस्सा (बजट)**

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सकल घरेलू उत्पाद के 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) के दौरान 7.2 प्रतिशत हो जाएगा। करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण सकल हस्तांतरण का सबसे बड़ा घटक है (चार्ट 16ए और बी)।

जबकि कर हस्तांतरण राजकोषीय हस्तांतरण की आधारशिला है, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) संरचनात्मक राजकोषीय अंतराल को पाटकर राज्य के वित्त को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (बॉक्स बी)।

बॉक्स बी: राजस्व घाटा अनुदान - राज्यों की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक साधन

वित्त आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व की कमी और लागत असमानताओं को कम करने का कार्य सौंपा गया है जो विभिन्न राज्यों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में बाधा डालते हैं (राव, 2022)। इस संदर्भ में, वित्त आयोग अनुदान राज्य-विशिष्ट राजकोषीय आवश्यकताओं जैसे आपदा राहत, स्थानीय निकायों का विकास, क्षेत्रीय निवेश और राजस्व घाटा समर्थन को लक्षित करने वाले सूत्र-आधारित कर हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में कार्य करता है। ये अनुदान कमजोर राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों को अत्यधिक उधार लिए बिना अपने व्यय दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें से, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) हस्तांतरण के बाद राजस्व की कमी को पूरा करके विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किए गए, आरडीजी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और राज्यों को आवश्यक शासन और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में सक्षम बनाने में मदद करते हैं।

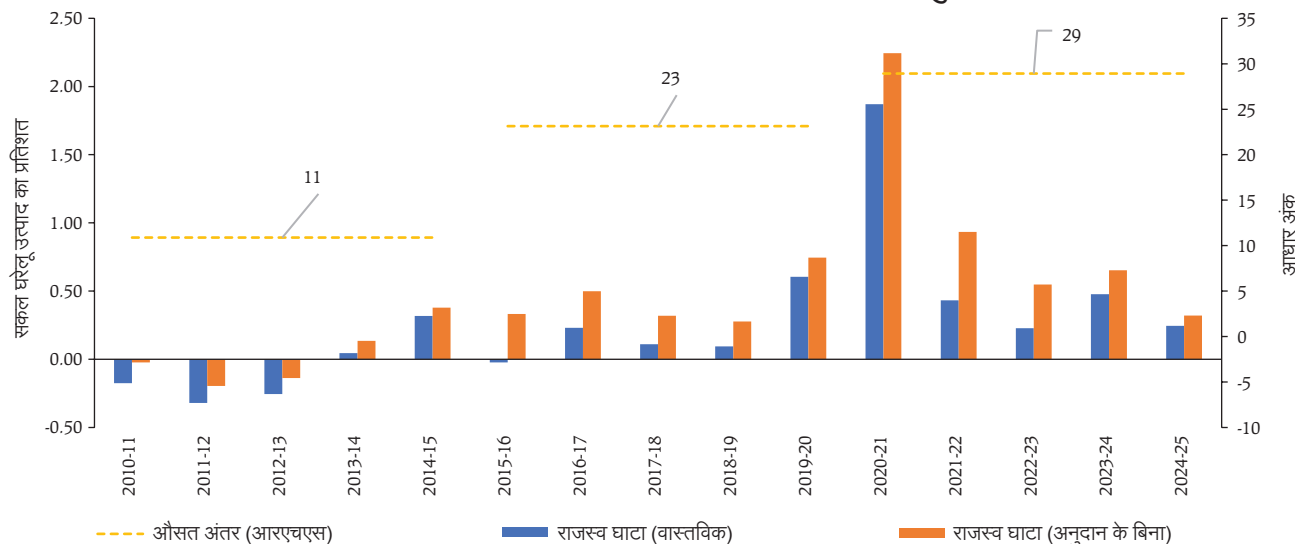
ऐतिहासिक रूप से, सभी वित्त आयोगों ने राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए आरडीजी की सिफारिश की है और राज्यों के राजस्व और व्यय अंतर के मानक आकलन के आधार पर इसे आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त, आरडीजी राज्यों को क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कर हस्तांतरण पैटर्न में परिवर्तनों के माध्यम से संक्रमण में मदद करते हैं। वे राज्यों को जरूरतों, राजकोषीय क्षमता और शासन प्रदर्शन (वित्त आयोग - XV) के उभरते आकलन के अनुरूप अपनी राजकोषीय स्थिति को समायोजित करने का समय देते हैं।

आरडीजी नैतिक जोखिम पैदा कर सकते हैं, जहां केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता राज्यों को महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधारों को लागू करने से हतोत्साहित करती है, जैसे कर प्रशासन में सुधार या व्यय युक्तिकरण। क्रमिक वित्त आयोगों ने प्रत्येक राज्य की राजकोषीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक मानक

(जारी)

⁸ विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें।

चार्ट बी.1: राज्यों का राजस्व घाटा: वास्तविक बनाम आर.डी. अनुदान के बिना



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और रिजर्व बैंक के राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन।

दृष्टिकोण अपनाकर इन चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। एक सरल अंतर-भरने के दृष्टिकोण के विपरीत, जो अनजाने में अपर्याप्त राजस्व प्रयास या अत्यधिक खर्च को पुरस्कृत कर सकता है, यह मानक ढांचा राजकोषीय क्षमता में संरचनात्मक कमियों को ठीक करता है जबकि राजकोषीय अपव्यय को हतोत्साहित करता है (रेड्डी और रेड्डी, 2019)। पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को समय के साथ अपने हस्तांतरण के बाद के राजस्व अंतराल को समाप्त करना चाहिए। नतीजतन, अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान पहले वर्ष में ₹1.18 लाख करोड़ से घटकर अपने पुरस्कार अवधि के अंतिम वर्ष में ₹13,705 करोड़ हो गया अनुदानों में चरणबद्ध कटौती से राज्यों को अपने हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए अपने राजकोषीय प्रबंधन में उपयुक्त समायोजन करने के लिए उचित समय मिलेगा (राव, 2021)।

आर.डी.जी. वाले और बिना आर.डी.जी. वाले राज्यों के समग्र राजस्व घाटे का विश्लेषण राज्य के वित्त पर उनके स्थिर प्रभाव को उजागर करता है। महामारी की शुरुआत ने राज्य के वित्त पर अतिरिक्त दबाव डाला, और आर.डी.जी. ने संबंधित राजकोषीय आघात को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर.डी.जी. के बिना, राज्यों को 2020-25 की अवधि (चार्ट बी.1) के दौरान 29 आधार अंकों से अधिक राजस्व घाटे का सामना करना

पड़ता, जिससे उधारी में वृद्धि या व्यय में कटौती की आवश्यकता होती, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और विकास व्यय कमजोर होता।

पिछले 15 वर्षों में, आरडीजी ने राज्यों को अपने घाटे को औसतन सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 से 0.3 प्रतिशत तक कम करने में मदद की है, जिससे अत्यधिक उधारी को रोका जा सका है और स्थिर सार्वजनिक व्यय को सक्षम किया जा सका है। आरडीजी सहित केंद्रीय हस्तांतरण, राजकोषीय संघवाद का समर्थन करने के लिए एक आवश्यक तंत्र बना हुआ है और राज्यों को राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

संदर्भ:

1. Government of India (2020). *Report of the Fifteenth Finance Commission. Volume I*. Ministry of Finance, Government of India.
2. Rao, M. G. (2021). Fiscal Transfers in Pandemic Times. *Economic and Political Weekly*, 56(33).
3. Rao, M. G. (2022). *Studies in Indian Public Finance*. Oxford University Press.
4. Reddy, Y. V., and Reddy, G. R. (2018). *Indian Fiscal Federalism*. Oxford University Press.
5. Various Finance Commission Reports.

सारणी 6: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त आयोग (एफसी) अनुदान

मद	₹ लाख करोड़		कुल एफसी अनुदान में हिस्सा (प्रतिशत में)		वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
वित्त आयोग (एफसी) अनुदान	1.3	1.3	-	-	-14.4	4.4
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	0.2	0.3	16.5	19.7	-1.1	24.6
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	0.5	0.5	35.4	36.6	-4.8	7.9
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	0.1	0.2	8.0	11.5	117.9	49.4
4. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	0.2	0.1	19.3	10.3	-52.6	-44.0
5. अन्य*	0.3	0.3	20.8	21.9	11.7	9.9

टिप्पणी: 'अन्य' में नए शहरों के विकास के लिए अनुदान, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अनुदान सहायता और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए अनुदान सहायता शामिल हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

वित्त आयोग ने 2025-26 में अनुदान में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए अनुदान में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान में वृद्धि है (सारणी 6)।

बजट में राज्यों के पूंजीगत व्यय और सुधार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शासन और नगरपालिका सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में, राज्यों को भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि के तहत पीपीपी परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में राज्य-स्तरीय बिजली वितरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रमुख बिजली क्षेत्र सुधारों का प्रस्ताव है। राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके समर्थन के लिए, सुधार करने वाले राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

राज्यों के साथ साझेदारी में कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों की घोषणा की गई है। कृषि में, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम और सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों की भागीदारी की मांग की गई है। जल जीवन

मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्र सरकार चुनौती-आधारित मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी करेगी। राज्यों को फंडिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे के लिए भूमि प्रदान करनी होगी।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस उद्देश्य की ओर, बजट ने विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के तहत नवाचार और संरचनात्मक सुधारों द्वारा प्रेरित कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने उपभोग बढ़ाने वाले उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था को अपनी विकास गति में सुधार करने में मदद मिलेगी। सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ, बजट समेकन और विकास उद्देश्यों को संतुलित करता है। सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आगे चलकर मध्यम अवधि के राजकोषीय लंगर के रूप में ऋण/जीडीपी अनुपात का उपयोग करेगी।

अनुलग्नक I: केंद्रीय बजट 2025-26 - प्रमुख राजकोषीय संकेतक

मद	₹ लाख करोड़					सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत			वृद्धि दर		
	2022-23	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. प्रत्यक्ष कर	1,660	1,956	2,207	2,237	2,520	6.6	6.9	7.1	17.9	14.4	12.7
(i) निगम	826	911	1,020	980	1,082	3.1	3.0	3.0	10.3	7.6	10.4
(ii) आय	809	1,011	1,150	1,202	1,360	3.4	3.7	3.8	25.0	18.8	13.1
(iii) प्रतिभूति लेनदेन कर	25	34	37	55	78	0.1	0.2	0.2	34.7	62.8	41.8
2. अप्रत्यक्ष कर	1,394	1,509	1,633	1,616	1,750	5.1	5.0	4.9	8.2	7.1	8.3
(i) जीएसटी	849	957	1,062	1,062	1,178	3.2	3.3	3.3	12.7	10.9	10.9
(ii) सीमा शुल्क	213	233	238	235	240	0.8	0.7	0.7	9.3	0.8	2.1
(iii) उत्पाद शुल्क	323	309	324	310	322	1.0	1.0	0.9	-4.2	0.2	3.9
3. सकल कर राजस्व (1+2)	3,054	3,466	3,840	3,853	4,270	11.7	11.9	12.0	13.5	11.2	10.8
4. राज्यों को असाइनमेंट	948	1,129	1,247	1,287	1,422	3.8	4.0	4.0	19.1	13.9	10.5
5. एनसीसीडी स्थानान्तरण	8	9	9	10	10	0.0	0.0	0.0	9.7	9.5	8.0
6. शुद्ध कर राजस्व (3-4-5)	2,098	2,327	2,583	2,557	2,837	7.9	7.9	7.9	10.9	9.9	11.0
7. गैर-कर राजस्व	285	402	546	531	583	1.4	1.6	1.6	40.8	32.2	9.8
(i) लाभांश और लाभ	100	171	289	289	325	0.6	0.9	0.9	71.0	69.3	12.3
(ii) ब्याज प्राप्ति	28	38	38	34	48	0.1	0.1	0.1	37.4	-11.0	40.2
8. राजस्व प्राप्ति (6+7)	2,383	2,729	3,129	3,088	3,420	9.2	9.5	9.6	14.5	13.2	10.8
9. गैर ऋण पूंजी प्राप्ति	72	60	78	59	76	0.2	0.2	0.2	-17.2	-1.3	28.8
(i) विविध पूंजी प्राप्ति	46	33	50	33	47	0.1	0.1	0.1	-28.1	-0.4	42.4
(ii) ऋण की वसूली	26	27	28	26	29	0.1	0.1	0.1	1.9	-2.4	11.5
10. कुल प्राप्ति (उधार को छोड़कर) (8+9)	2,455	2,789	3,207	3,147	3,496	9.4	9.7	9.8	13.6	12.8	11.1
11. राजस्व व्यय (आरई)	3,453	3,494	3,709	3,698	3,944	11.8	11.4	11.0	1.2	5.8	6.7
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	929	1,064	1,163	1,138	1,276	3.6	3.5	3.6	14.6	7.0	12.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस)	578	435	428	428	426	1.5	1.3	1.2	-24.7	-1.6	-0.4
जिसका कि:											
खाना	273	212	205	197	203	0.7	0.6	0.6	-22.4	-6.8	3.0
उर्वरक	251	188	164	171	168	0.6	0.5	0.5	-25.1	-9.0	-2.0
पेट्रोलियम	7	12	12	15	12	0.0	0.0	0.0	79.5	20.1	-17.7
(iii) आरई-आईपी-टीएस	1,947	1,995	2,118	2,132	2,242	6.8	6.6	6.3	2.5	6.9	5.1
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	740	949	1,111	1,018	1,121	3.2	3.1	3.1	28.3	7.3	10.1
(i) पूंजीगत परिव्यय	625	788	919	848	895	2.7	2.6	2.5	26.1	7.6	5.6
(ii) ऋण एवं अग्रिम	115	161	192	171	226	0.5	0.5	0.6	39.8	6.0	32.3
13. कुल व्यय (11+12)	4,193	4,443	4,821	4,716	5,065	15.0	14.6	14.2	6.0	6.1	7.4
14. सकल राजकोषीय घाटा (13-10)	1,738	1,655	1,613	1,570	1,569	5.6	4.8	4.4	-4.8	-5.1	-0.04

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

अनुलग्नक II: केंद्र से राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण

मद	₹ लाख करोड़			सकल हस्तांतरण के प्रतिशत के रूप में			वृद्धि दर		
	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण	1,129	1,287	1,422	54.7	56.6	55.6	19.1	13.9	10.5
II. वित्त आयोग अनुदान	148.5	127.1	132.8	7.2	5.6	5.2	-14.0	-14.4	4.4
जिसका कि:									
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	21.2	21.0	26.2	1.0	0.9	1.0	19.2	-1.1	24.6
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	47.3	45.0	48.6	2.3	2.0	1.9	3.6	-4.8	7.9
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	4.7	10.2	15.3	0.2	0.4	0.6	42.2	117.9	49.4
4. एसडीआरएफ के लिए अनुदान सहायता	19.4	20.6	21.6	0.9	0.9	0.8	18.4	5.8	5.0
5. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए अनुदान सहायता	4.3	5.1	5.4	0.2	0.2	0.2	21.5	20.8	5.0
6. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	51.7	24.5	13.7	2.5	1.1	0.5	-40.1	-52.6	-44.0
III. स्थानांतरण की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएँ	160.3	201.1	229.0	7.8	8.8	8.9	33.1	25.5	13.9
जिसका कि:									
1. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ-ऋण	31.3	34.4	42.7	1.5	1.5	1.7	11.0	9.9	24.2
2. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	109.6	125.0	150.0	5.3	5.5	5.9	34.9	14.1	20.0
3. मांग के अंतर्गत विशेष सहायता - राज्यों को हस्तांतरण	11.7	18.0	10.0	0.6	0.8	0.4	408.5	53.9	-44.4
IV. राज्यों को कुल स्थानांतरण [I+II+III के अलावा]	571.3	604.5	717.0	27.7	26.6	28.0	0.8	5.8	18.6
1. केंद्र प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)	425.3	392.7	514.4	20.6	17.3	20.1	4.8	-7.7	31.0
2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	15.1	63.8	76.5	0.7	2.8	3.0	17.0	322.5	20.0
3. व्यय की अन्य श्रेणियाँ	131.0	147.9	126.0	6.3	6.5	4.9	-11.6	12.9	-14.8
4. पूंजी हस्तांतरण	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-50.0	10100.0	1.0
V. दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को स्थानांतरण	55.2	55.9	58.5	2.7	2.5	2.3	-1.8	1.3	4.5
VI. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सकल स्थानान्तरण (I+II+III+IV+V)	2,065	2,276	2,560	100.0	100.0	100.0	10.7	10.2	12.5
VII. ऋण और अग्रिम की वसूली घटा दी गई	12.2	50.3	50.3	0.6	2.2	2.0	21.0	311.1	0.0
VIII. शुद्ध स्थानान्तरण (VI-VII)	2,053	2,225	2,510	99.4	97.8	98.0	10.7	8.4	12.8
IX. सकल स्थानान्तरण / जीडीपी (प्रतिशत)	7.0	7.0	7.2						
X. शुद्ध स्थानान्तरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.9	6.9	7.0						

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।